नोहिरिया राम

बनाम

भारत संघ और अन्य

(संबद्ध अपील के साथ)

(मुख्य न्यायाधिपति श्री एस.आर. दास, न्यायमूर्ति श्री वेंकटरामा अय्यर, न्यायमूर्ति श्री एस.के.दास, न्यायमूर्ति श्री ए.के.सरकार और न्यायमूर्ति श्रीविवियन बोस)

सिविल सेवक-संवर्ग-नियमित स्थापना के लिए अतिरिक्त पद-चाहे नियमित कैडर-पद सृजन का अभिन्न अंग है संवर्ग-क्षमता से बाहर-ऐसे पद पर पदस्थ व्यक्ति का स्थानांतरण विदेशी सेवा-प्रभाव-मौलिक नियमों पर, आरआर। 9(4),111,113,127-सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियम, आरआर. 24, 44।

अपीलकर्ता मूल रूप से सिविलियन क्लर्क के रूप में रॉयल एयर फोर्स, क्वेटा में कार्यरत था। लेकिन बाद में उनके द्वारा भारतीय चिकित्सा सेवा के महानिदेशक को किए गए आवेदन पर, उन्हें भारतीय अनुसंधान कोष संघ के काम को निपटाने के लिए महानिदेशक के कार्यालय में एक अतिरिक्त क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था, इस आधार पर कि छुट्टी और पेंशन संबंधी योगदान के साथ नियुक्ति की औसत लागत संघ से वसूल

किया जानी थी। लोक सेवा आयोग ने इस शर्त पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी कि इससे उन्हें केंद्रीय सचिवालय या उससे जुड़े कार्यालयों में नियुक्ति का कोई दावा नहीं मिलेगा। 12 जून, 1930 को, अपीलकर्ता को 1 अप्रैल, 1930 से अतिरिक्त पद पर पुष्टि की गईऔर 10 अप्रैल, 1931 को उन्हें भारतीय अनुसंधान कोष संघ के तहत ''विदेशी सेवा'' पर स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने 17 सितंबर, 1944 तक सेवा जारी रखी। परिणामस्वरूप उनके द्वारा किए गए कुछ अभ्यावेदन जिसमें उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिस पद पर वे थे वह स्थायी पद था। महानिदेशक, भारतीय की नियमित स्थापना चिकित्सा सेवा को जारी रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि अतिरिक्त संवर्ग केपद पर बने रहने के दौरान, जिसेमूल रूप से भारतीय अनुसंधान कोष संघ के काम के लिए स्वीकृत किया गया था, वे भविष्य में महानिदेशक के कार्यालय में सामान्य काम पर कार्यरत रहेंगे, लेकिन मौजूदा अयोग्यताओं के अधीन बने रहेंगे, अर्थात कार्यालय के मंत्रालिक नियमित संवर्ग में नियुक्ति के लिए कोई दावा नहंी होगा। उन्होने 30 मार्च 1948 को भारत संघ के खिलाफ मुकदमा दायर किया, कि वे महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा के कार्यालय के नियमित मंत्रालिक संस्थान के स्थायी सदस्य के रूप में भारत संघ की सेवा में थे। उन्होने तर्क दिया कि अन्य बातों के साथ-साथ (1) वह पद जिसमें उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, 1930 में एक अलग संवर्ग में गठित नहीं किया गया था, उस पद को महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा की

नियमित स्थापना के अतिरिक्त माना जाना चाहिए और इसके अलावा, एक ही संवर्ग का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और (2) किसी भी मामलें में, मौलिक नियमों में ''विदेश सेवा'' से संबंधित नियमों के तहत, नियमित संस्थान के सदस्यों को केवल ''विदेश सेवा'' पर भेजा जा सकता है और जैसा कि सरकार ने'' ''

दी थी, उसे महानिदेशक की नियमित स्थापना का सदस्य माना जाना चाहिए।

अभिनिर्धारित, (1) कि यह अनुमोदन की क्षमता के भीतर था- किसी विशेष कार्यालय के नियमित संवर्ग के बाहर एक अतिरिक्त पद बनाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी, जिसमें प्रशासनिक नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए पद संलग्न किया जाए, और मौलिक नियम 127 केवल उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिनके अनुसार अतिरिक्त पद की लागत वसूल की जाएगी।

(2) मौलिक नियम 113 लागू नहीं था, इस मामले में अपीलार्थी स्थानांतरण से पहले ''विदेश सेवा'' पर किसी संवर्ग से संबंधित नहीं था।

प्रश्न यह है कि क्या यह लोक सेवा आयोग के लिए खुला था, किसी शर्त को लागू करने या सशर्त देने के लिए आयोग अपीलकर्ता की नियुक्ति पर सहमति को खुला छोड दिया गया था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 1957 की सिविल अपील संख्या 116 और 117।

1951 की सिविल नियमितप्रथम अपील संख्या 190 और 1952 की सिविल रिट संख्या 82. डी में दिल्ली में पंजाब उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के 30 अक्टूबर, 1953 के फैसले और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से डीआर प्रेम. टीएस वेंकटरमन और केआर चौधरी।

उत्तरदाताओं के लिए आर.गणपति अय्यर. पोरस ए. मेहता और आरएच ढेबर।

8 नवम्बर, 1957 न्यायालय का फैसला एसके दास जे द्वारा सुनाया गया। ये विशेष अनुमति द्वारा दो अपीलें हैं। पं. नोहिरिया राम दोनों अपीलों में अपीलकर्ता हैं। उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका (याचिका संख्या 397/1955) भी दायर की थी । संविधान के अनुच्छेद 32 जिसमें उन्होंने भारत संघ, प्रतिवादी 1 और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली, प्रतिवादी 2 को पक्षकार रखा, एक उपयुक्त रिट जारी करने की प्रार्थना की थी, 3 अक्टूबर, 1955 को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी 2 द्वारा बर्खास्तगी पारित की गई। हालाँकि, उस याचिका को वापस लेते हुए

खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान निर्णय दो अपीलों तक ही सीमित है, और उनसे संबंधित प्रासंगिक तथ्य नीचे बताए गए हैं।

पूर्व में, अपीलकर्ता की रॉयल एयर फोर्स, नंबर 3 (भारतीय) विंग, क्वेटा के कार्यालय में एक सिविलियन क्लर्क के रूप में स्थायी नियुक्ति थी। 17 मार्च, 1928 को उन्होंने महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा, नई दिल्ली (अब महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली के रूप में जाना जाता है) के कार्यालय में एक क्लर्कके पद के लिए आवेदन किया। अपीलकर्ता अपने आवेदन में सफल हो गया और 28 मार्च, 1928 को उसे बताया गया कि महानिदेशक के कार्यालय में ग्रेड रुपये 75-4-155 में एक रिक्ति थी। आगे कहा गया कि नियुक्ति पहली बार में एक वर्ष के लिए होगी, हालाँकि इसके स्थायी होने की संभावना थी, और यदि अपीलकर्ता पद स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया, तो उसे 16 अप्रैल, 1928 को शिमला में महानिदेशक के कार्यालय में शामिल होने का निर्देश दिया गया। अपीलकर्ता को ग्रहणाधिकार देने के लिए रॉयल एयर फोर्स के अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया था। 28 फ़रवरी, 1929 तक रॉयल एयर फ़ोर्स में उनका स्थायी पद था, जिस तिथि तक महानिदेशक के कार्यालय में नियुक्ति की स्थायीता का प्रश्न तय किया जाना था। अपीलकर्ता ने 16 अप्रैल, 1928 को अपने रिक्त पद पर जाॅइन किया। 26 फरवरी, 1930 को, भारत सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग, जो अब तक महानिदेशक, भारतीय

चिकित्सा सेवा के कार्यालय के रूप में नियंत्रण विभाग था, द्वारा अपीलकर्ता को 1 अप्रैल, 1930 से महानिदेशक के कार्यालय में रुपये के ग्रेड में एक अतिरिक्त क्लर्क की नियुक्ति को मंजूरी ग्रेड 75-4-155 पर दे दी गई। इस समझ के साथ भारतीय अनुसंधान निधि एसोसिएशन के काम से निपटने के लिए कि छुट्टी और उस पर पेंशन योगदान के साथ नियुक्ति की औसत लागत एसोसिएशन से वसूल की जानी थी। 30 अप्रैल, 1930 को, महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा, ने सचिव, लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर सूचित किया कि भारतीय अनुसंधान निधि एसोसिएशन के काम के लिए भारत सरकार द्वारा एक अतिरिक्त क्लर्क की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई थी, महानिदेशक ने तब कहा कि अतिरिक्त पद का पदधारी अपीलकर्ता था, जो पहले रॉयल एयर फोर्स, क्वेटा में एक स्थायी पद पर था और चूंकि वह लोक सेवा आयोग से उत्तीर्ण होने वाला उम्मीदवार नहीं था, इसलिए आयोग से कहा गया था कि उक्त पद पर उनकी स्थाई नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करें। इस पर सचिव, लोक सेवा आयोग ने निम्नलिखित उत्तर दिया

> "आपके पत्र संख्या 219/516 दिनांक 30 अप्रैल 1930, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोक सेवा आयोग को अस्थायी क्लर्क की पुष्टि पर कोई आपत्ति नहीं है

> जो वर्तमान में भारतीय अनुसंधान के काम पर कार्यरत है फंड एसोसिएशन इस शर्त के अधीन है कि इससे उन्हें सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में रूटीन डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्ति का कोई दावा नहीं मिलेगा।''

लोक सेवा आयोग का यह उत्तर अपीलकर्ता को दिखाया गया था और उसे विशेष रूप से इस शर्त पर ध्यान देने के लिए कहा गया था कि सचिवालय या संलग्न कार्यालयों, महानिदेशक, भारतीय के कार्यालय में नियमित डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्ति के लिए उसका कोई दावा नहीं होगा, चिकित्सा सेवा, सचिवालय से जुड़ा एक कार्यालय है। 26 मई, 1930 को अपीलकर्ता ने लोक सेवा आयोग का पत्र देखा और नोट किया. ''देखा, धन्यवाद''। 12 जून, 1930 को, अपीलकर्ता को 1 अप्रैल, 1930 से अतिरिक्त पद पर स्थायी कर दिया गया। 10 अप्रैल, 1931 को, अपीलकर्ता को ग्रेड में द्वितीय श्रेणी सहायक के रूप में भारतीय अनुसंधान निधि एसोसिएशन के तहत विदेशी सेवा में स्थानांतरित कर दिया गया, ग्रेड रुपये का 120-8-160-10-350 इस शर्त पर कि एसोसिएशन छुट्टी और पेंशन योगदान आदि के साथ पद की औसत लागत का भुगतान करना जारी रखेगा। अपीलकर्ता 17 सितंबर 1944 तक भारतीय अनुसंधान निधि एसोसिएशन के तहत काम करता रहा।

कुछ छोटी अवधियों के लिए ब्रेक लिया, जिसके दौरान वह महानिदेशक के कार्यालय में कार्य करने के लिए लौट आए सहायक, प्रथम श्रेणी या विशेष श्रेणी, रु. 200-12-440, 10 जून, 1932 को, गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल ने 10 अप्रैल, 1931 से अपीलकर्ता को भारतीय अनुसंधान निधि एसोसिएशन के तहत विदेशी सेवा में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी। 15 अगस्त, 1944 को, अपीलकर्ता ने सचिव को एक अभ्यावेदन दिया। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें उनके मूल कार्यालय में वापस कर दिया जाए। कारण यह दिया गया कि अपीलकर्ता के साथ ''उदासीनतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा था और अतीत में कुछ गलतफहमियाँ रही थीं और भविष्य में भी ऐसी ही गलतफहमियाँ हो सकती हैं।'' 11 सितंबर, 1944 को, भारतीय अनुसंधान निधि एसोसिएशन के सचिव ने अपीलकर्ता को यह कहने के लिए लिखा कि महानिदेशक के कार्यालय में प्रत्यावर्तन के लिए उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और अपीलकर्ता को महानिदेशक के कार्यालय में वापस लौट जाना चाहिए, 18 सितंबर, 1944, से चूंकि महानिदेशक की पिछली सहमति प्रत्यावर्तन के लिए प्राप्त नहीं की गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ परेशानी हुई और महानिदेशक ने अपीलकर्ता को भारतीय अनुसंधान निधि एसोसिएशन में ड्यूटी के लिए खुद को रिपोर्ट करने के लिए कहा। इसके बाद अपीलकर्ता ने नवंबर 1944 और जनवरी 1945 में कुछ अभ्यावेदन दिए, जिसमें उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिस पद पर वह कार्यरत

थे, वह महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा की नियमित स्थापना में एक स्थायी पद था, और उन्हें वापस लौटने पर उसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। मूल कार्यालय, एक वरिष्ठ सहायक के रूप में जो महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा की नियमित स्थापना के एक स्थायी सदस्य को उपलब्ध सभी वेतन वृद्धि और पदोन्नति का हकदार था। इन अभ्यावेदनों पर अपीलकर्ता को निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुआः

“सचिव, आईआरएफए के हालिया संचार के जवाब में, भारत सरकार, ईएच.एंड.एल.विभाग ने पुष्टि की कि श्री नोहिरिया राम उनके पत्र संख्या एफ.9.22/39-एच में निहित आदेशों द्वारा शासित थे। दिनांक 8 अगस्त, 1939, और संख्या एफ. 37-13/41-एच, दिनांक 27 नवंबर, 1941 इन आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है.-

(1) कि श्री नोहिरिया राम का मूल पद इस कार्यालय से जुड़ा हुआ है आईआरएफए का कार्य देखने के लिए;

(2) कि यह इस कार्यालय के नियमित कैडर से बाहर है;

(3)कि श्री नोहिरिया राम को उस संवर्ग में रिक्ति होने पर इस कार्यालय के नियमित संवर्ग में समाहित नहीं किया जाना चाहिए; और

(4) यह पद श्री नोहिरिया राम के सेवानिवृत्त होने तक इस संवर्ग के बाहर बरकरार रखा जाना चाहिए।

श्री नोहिरिया राम को उपरोक्त पद पर तभी स्थायी किया गया जब उन्होंने लिखित रूप से यह शर्त स्वीकार कर ली कि इस कार्यालय की नियमित स्थापना पर किसी पद पर उनका कोई दावा नहीं होगा। यह शर्त इसलिए लगाई गई क्योंकि वह एक ''अयोग्य क्लर्क' है।

हालाँकि, अपीलकर्ता इस आदेश से असंतुष्ट था और उसने आगे अभ्यावेदन देना जारी रखा और अंततः 17 दिसंबर, 1945 को, उसने भारतीय अनुसंधान निधि एसोसिएशन के कार्यालय में काम करने में असमर्थता व्यक्त की, जिसे उसने ''निजी निकाय'' के रूप में वर्णित किया था, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को 14 दिसंबर, 1945 से निलंबित कर दिया गया था, जिस तारीख को उसे महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा के कार्यालय से जुड़े क्लर्क के पद पर अपने काम में शामिल होना था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन का काम देखने। 10 जनवरी, 1946 को अपीलकर्ता को एक आरोप पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि दस दिनों की छुट्टी समाप्त होने पर, उन्होंने महानिदेशक के कार्यालय से जुड़े क्लर्कके अपने मूल पद पर ड्यूटी पर लौटने से इनकार कर दिया था। भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय अनुसंधान निधि एसोसिएशन के कार्य के लिए। अपीलकर्ता ने एक लिखित बयान प्रस्तुत किया और कुछ और अभ्यावेदन दिए। 5 सितंबर, 1946 को निलंबन आदि आदेशों को संशोधित किया गया और निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

''श्री नोहिरिया राम को सूचित किया गया है कि इस विषय पर मौजूदा आदेशों को संशोधित करते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अतिरिक्त कैडर पद जो मूल रूप से आईआरएफए के काम के लिए स्वीकृत किया गया था, को जारी रखते हुए भविष्य में उन्हें इस पर नियोजित किया जाएगा। इस कार्यालय का सामान्य कार्य, वह मौजूदा अयोग्यताओं के अधीन रहेगा, अर्थात्, उसे सचिवालय या उससे जुड़े कार्यालयों में नियमित डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्ति या मंत्रालयिक प्रतिष्ठान के नियमित कैडर में शामिल होने का कोई दावा नहीं होगा। इस कार्यालय के। उपरोक्त निर्णय के अनुसार,

श्री नोहिरिया राम को तत्काल शिमला स्थित इस कार्यालय में कैप्टन जेएम. रिचर्डसन, डीएडीजी (पी) को ड्यूटी के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। उन्हें भारतीय चिकित्सा समीक्षा अनुभाग में तैनात किया जाएगा''

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने शिमला में जाॅइन कर लिया और 30 मार्च, 1948 को, उसने भारत संघ के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें यह घोषणा करने के लिए कहा गया कि वह स्थायी नियमित सदस्य के रूप में भारत संघ की सेवा महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा के कार्यालय की मंत्रालिक स्थापना में है। उन्होंने कुछ अन्य राहतों का भी दावा किया, जिन्हें हालाँकि छोड़ दिया गया। इस मुकदमे का डिक्री करते हुए फैसला 10 मार्च, 1951 को दिल्ली के विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा किया गया था। भारत संघ ने एक अपील दायर की, जो 1951 की प्रथम अपील संख्या 190 थी। इस अपील को पंजाब उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर के अपने फैसले द्वारा अनुमति दी थी। 1953. परिणाम यह हुआ कि अपीलकर्ता का मुकदमा खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता ने पंजाब उच्च न्यायालय से इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए एक प्रमाण पत्र मांगा। वह आवेदन अस्वीकार कर दिया गया, अपीलकर्ता ने तब इस न्यायालय का रुख किया और विशेष अनुमति प्राप्त की, और 1957 की सिविल अपील संख्या 116 इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति के अनुसरण में दायर की गई है और यह 1951 की प्रथम अपील संख्या 190 में पंजाब उच्च न्यायालय के 30 अक्टूबर, 1953 के फैसले और डिक्री के खिलाफ प्रस्तुतहै।

1957 की सिविल अपील संख्या 117 अपीलकर्ता की कथित शिकायतों

की कहानी को जारी रखती है, जब उसने दिल्ली के विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश से अपनी डिक्री प्राप्त कर ली थी। हमने पहले कहा है कि उस डिक्री के खिलाफ भारत संघ ने 24 जुलाई, 1951 को एक अपील दायर की थी। उस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने कला के तहत एक याचिका के माध्यम से पंजाब उच्च न्यायालय का रुख किया । संविधान के 226 में एक रिट जारी करने के लिए महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली को निर्देश दिया गया कि वह वेतन और भत्ते तुरंत वितरित करें, जिसके लिए अपीलकर्ता नवंबर, 1952 के महीने के लिए हकदार था। ऐसा हुआ कि अक्टूबर, 1952 में, अपीलकर्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग 1 में कार्यरत था, और 3 अक्टूबर, 1952 को, वह 11 अक्टूबर, 1952 तक औसत वेतन पर छुट्टी पर चला गया। 13 अक्टूबर, 1952 को छुट्टी से लौटने पर, उसने एक आवेदन प्रस्तुत किया। ज्वाइनिंग रिपोर्ट और पोस्टिंग ऑर्डर मांगे। उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग प् में काम करने के लिए कहा गया था, जहाँ से वह छुट्टी पर चले गए थे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और महानिदेशक से साक्षात्कार के लिए कहा। इसे अस्वीकार कर दिया गया,और अपीलकर्ता को बताया गया कि जब तक वह सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग प् में ड्यूटी पर वापस नहीं आता, उसे बिना अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित माना जाएगा। अपीलकर्ता अभी भी उसी अड़ियल रवैये पर कायम है जो उसने अपनाया था, संभवतः इस विश्वास में कि उसके पक्ष में डिक्री के बाद वह नियमित प्रतिष्ठान के स्थायी सदस्य के

लिए उपलब्ध सभी पदोन्नति और वेतन वृद्धि का हकदार था। वह कार्यालय आये, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग 1 में जाने के बजाय, उन्होंने सामान्य अनुभाग में रिकॉर्ड सॉर्टर के लिए बनी सीट पर कब्जा कर लिया। दूसरे शब्दों में, 13 अक्टूबर 1952 के बाद से अपीलकर्ता ने कोई कार्य नहीं किया। उन्हें अक्टूबर, 1952 के अंत तक वेतन का भुगतान किया गया था, लेकिन नवंबर, 1952 के लिए भुगतान रोक दिया गया था। 20 दिसंबर, 1952 को अपीलकर्ता ने अनुच्छेद 226 के तहत अपनी याचिका दायर की उसी तारीख को जिस दिन भारत संघ की अपील की अनुमति दी गई थी, अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन, जिसमें पंजाब उच्च न्यायालय ने भी इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अपीलकर्ता अवज्ञा और अपमानजनक आचरण का दोषी था और किसी भी राहत का हकदार नहीं था। इस आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता ने इस न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद, 1957 की सिविल अपील 117 दायर की है।

इन दो अपीलों में निर्णय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता ने महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा, नई दिल्ली के कार्यालय के स्थायी और नियमित मंत्रालिक प्रतिष्ठान में कोई पद धारण किया है। उच्च न्यायालय ने माना है कि जिस पद पर अपीलकर्ता को स्थायी किया गया था, वह निस्संदेह भारतीय अनुसंधान निधि संघ के कार्य के उद्देश्य से महानिदेशक के कार्यालय से जुड़ा एक पद था, लेकिन यह

नियमित कैडर के बाहर का पद था, महानिदेशक के कार्यालय में, और यह अपीलकर्ता को शुरू से ही स्पष्ट कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता जानता था और उसने उन शर्तों को स्वीकार नहीं किया था जिन पर उसे नियुक्त किया गया था और लगभग 14 वर्षों के अंतराल के बाद उन्होंने जो शिकायत की वह निराधार और काल्पनिक थी।

अपीलकर्ता के विद्वानअधिवक्ता ने उपरोक्त निष्कर्षों की सत्यता पर विवाद किया है। यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता को वह शर्त पता थी जो लोक सेवा आयोग ने 16 मई, 1930 को अपीलकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी देते समय लगाई थी। हमारे सामने तर्क यह है (1) कि प्रासंगिक नियमों के सही निर्माण पर और अपीलकर्ता की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले सरकारी आदेश, 1 अप्रैल, 1930 से उनकी पुष्टि पर अपीलकर्ता, महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा के कार्यालय की नियमित स्थापना का स्थायी सदस्य बन गया, और (2) कि लोक सेवा आयोग को उन नियमों और आदेशों के निरादर में कोई शर्त लगाने का अधिकार नहीं था।

आइए अब उन नियमों और आदेशों की जांच करें जिन पर अपीलकर्ता भरोसा करता है। मौलिक नियम 9(4) बताता है कि कैडर का क्या मतलब है। इसका मतलब वास्तव में एक अलग इकाई के रूप में स्वीकृत किसी प्रतिष्ठान या सेवा ''बाद में सेवा के एक हिस्से को शामिल करने के लिए संशोधि''

प्रतिष्ठान से संबंधित हैं वह महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा के कार्यालय की स्थापना है। उस प्रतिष्ठान की कुल स्वीकृत संख्या 30 थी। 26 फरवरी, 1930 के अपने पत्र में, भारत सरकार ने इस समझ के आधार पर भारतीय अनुसंधान निधि एसोसिएशन के काम से निपटने के लिए एक अतिरिक्त क्लर्क की नियुक्ति को इस शर्त पर मंजूरी दे दी कि पद की लागत और छुट्टी तथा पेंशन अंशदान की वसूली एसोसिएशन से की जाएगी। सवाल यह है कि क्या यह अतिरिक्त पद नियमित संवर्ग की स्थायी वृद्धि थी या संवर्ग से बाहर का पद था। 1934 में महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व ने सवाल उठाया और महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा से पूछताछ की कि उनके प्रतिष्ठान में केवल 30 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 31 व्यक्तियों का वेतन कैसे दिखाया गया। महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा ने उत्तर दिया कि संख्या 31 में अतिरिक्त क्लर्क का पद शामिल है, हालाँकि यह पद उनके कार्यालय की स्वीकृत संख्या में शामिल नहीं था। 1935 में भारतीय चिकित्सा सेवा के महानिदेशक ने सरकार को पत्र लिखा और कहाः ''व्यवहारिक रूप से यह पद तब से मेरे कार्यालय के नियमित कैडर के बाहर माना जाता है।'' भारतीय चिकित्सा सेवा के महानिदेशक ने फिर कहाः

> ''मैं मानता हूं कि एफआर 127 ही एकमात्र नियम है जिसके तहत निजी निकायों के कार्य के निष्पादन के लिए

एक नियमित प्रतिष्ठान में परिवर्धन किया जा सकता है। चूंकि यह नियम एक और एक ही में दो अलग-अलग प्रतिष्ठानों के गठन पर विचार नहीं करता है। कार्यालय में मेरी राय है कि विचाराधीन दो पदों को मेरे कार्यालय की ताकत में वृद्धि के रूप में माना जाना चाहिए और इस तरह वे मेरे प्रशासनिक नियंत्रण में रहना चाहिए।''

इस पत्र पर भारत सरकार ने इस आशय का उत्तर दिया कि यद्यपि यह पद महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा के प्रशासनिक नियंत्रण में था, यह नियमित स्थापना के बाहर का पद था और इस पद के पदधारियों के साथ-साथ किसी अन्य समान पद के पदधारियों को भी ऐसा करना चाहिए। भविष्य में रिक्तियां होने पर नियमित स्थापना में समाहित किया जाएगा। इस आदेश को 1939 में आंशिक रूप से संशोधित किया गया था जब यह कहा गया थाः ''भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय अनुसंधान निधि संघ के काम के लिए आपके कार्यालय से जुड़े क्लर्क का पद, जो आपके कार्यालय के नियमित कैडर से बाहर है, को नहीं भेजा जाना चाहि'' ' रिक्ति होने पर उस संवर्ग में समाहित कर लिया जाएगा । जब तक श्री नोहिरिया राम भारतीय अनुसंधान निधि संघ के अधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहेंगे तब तक इसे संवर्ग से बाहर यथावत रखा जाना चाहिए तथा संघ को अवकाश का भुगतान जारी रखना चाहिए

और बाद के पद के कारण सरकार को पेंशन योगदान।

श्री नोहिरिया राम के अपने मूल पद पर लौटने की स्थिति में, जैसा कि मूल रूप से इस विभाग के पत्र संख्या 467-एच, दिनांक 26 फरवरी, 1930 में निर्धारित किया गया था, एसोसिएशन को इसकी आवश्यकता होगी। पद की औसत लागत और छुट्टी और पेंशन योगदान का भुगतान करने के लिए। श्री नोहिरिया राम की सेवा से सेवानिवृत्ति पर पद समाप्त कर दिया जाएगा।''

उपरोक्त आदेशों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस पद पर अपीलकर्ता को 1930 में स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, वह महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा के नियमित स्थापना के कैडर के बाहर का पद था। दरअसल, 2 अप्रैल, 1935 कोए गृह विभाग (जैसा कि तब इसे कहा जाता था) ने अपने संदर्भ में फैसला सुनाया कि ''महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा के मंत्रालयिक कर्मचारियों की संख्या, वास्तविक में दो पदों को छोड़कर थी, जिसमें से इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन से प्राप्त किया गया था''

अपीलकर्ता के मामले का मुख्य आधार, जैसा कि उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, धारा 111, अध्याय ग्प्प् में मौलिक नियम 127 है, जिसे सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 के नियम 24 और 44 के साथ पढ़ा जाता है। यह तर्क दिया गया है

कि वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमों के तहत काउंसिल में गवर्नर जनरल महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा की स्थापना की स्वीकृत शक्ति की घोषणा करके कैडर का गठन करने के लिए अकेले सक्षम थे और मौलिक नियम 127 निर्धारित करता है जब निजी व्यक्तियों या निकायों के लाभ के लिए एक नियमित प्रतिष्ठान में वृद्धि की जाती है तो लागत की वसूली कैसे की जाएगी, और तर्क यह बताता है कि जिस पद पर अपीलकर्ता को 1930 में स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था वह गठित नहीं था एक अलग कैडर में, उस पद को महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा की नियमित स्थापना के अतिरिक्त माना जाना चाहिए और इसलिए, उसी कैडर का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। हम इस तर्क को सही नहीं मान पा रहे हैं, यह सच है कि जिस अतिरिक्त पद पर अपीलकर्ता को स्थायी किया गया था, उसे एक अलग कैडर में गठित नहीं किया गया था। स्पष्ट कारण यह था कि यह नियमित कैडर के बाहर एक अतिरिक्त पद था। जिन नियमों की ओर विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उनमें से कोई भी नियम उपयुक्त प्राधिकारी को किसी विशेष कार्यालय के नियमित कैडर के बाहर एक अतिरिक्त पद बनाने से नहीं रोकता है, जिसके साथ प्रशासनिक नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए पद संलग्न किया जा सकता है। एफआर 127 जिस पर विद्वान अधिवक्ता ने इतना भरोसा किया है वह इन शर्तों में हैः एफआर 127ण् ष्जब किसी नियमित प्रतिष्ठान में इस शर्त पर कोई वृद्धि की जाती है कि इसकी लागत, या इसकी लागत का एक

निश्चित हिस्सा, व्यक्तियों से वसूल किया जाएगा जिसके लाभ के लिए अतिरिक्त प्रतिष्ठान बनाया गया है, उसकी वसूली निम्नलिखित नियमों के तहत की जाएगीः

(ए) वसूल की जाने वाली राशि सेवा की सकल स्वीकृत लागत, या सेवा के हिस्से, जैसा भी मामला हो, होगी और किसी भी महीने के वास्तविक व्यय के से भिन्न नहीं होगी।

(बी) सेवा की लागत में ऐसी दरों पर योगदान शामिल होगा जो नियम 116 के तहत निर्धारित की जा सकती हैं और योगदान की गणना प्रतिष्ठान के सदस्यों के वेतन की स्वीकृत दरों पर की जाएगी।

(सी) एक स्थानीय सरकार वसूली की मात्रा कम कर सकती है या उन्हें पूरी तरह से छोड़ सकती है।''

नियम अनुच्छेद 783 से मेल खाता है, सिविल सेवा विनियम के अध्याय ग्स्प् में उल्लेखित है, और उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिनके अनुसार अतिरिक्त पद की लागत, या लागत का एक निश्चित हिस्सा वसूल किया जाएगा । यह इस प्रश्न का निर्णय नहीं करता कि पद कैडर का हिस्सा है या नहीं। यह उपयुक्त प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करता है, और हम जानते हैं कि वर्तमान मामले में उपयुक्त प्राधिकारी ने शुरू से ही निर्णय लिया था कि अपीलकर्ता के पास जो अतिरिक्त पद था वह

महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा की नियमित स्थापना के बाहर था।

आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रासंगिक नियमों के तहत केवल नियमित प्रतिष्ठान के सदस्यों को ही विदेश सेवा पर भेजा जा सकता है और जैसा कि स्वीकृत है कि सरकार ने 10 अप्रैल, 1931 से अपीलकर्ता के विदेशी सेवा में स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है, अपीलकर्ता को माना जाना चाहिए महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा के नियमित प्रतिष्ठान का सदस्य। हमारी राय में यह तर्क भी उतना ही भ्रामक है। ''विदेश सेवा'' से संबंधित नियम धारा प्प्प्ए अध्याय ग्प्प् में पाए जाते हैं और जिन विशेष नियमों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है वे मौलिक नियम 111 और 113 हैं। जहाँ तक यह हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, मौलिक नियम 111 कहता है कि विदेशी सेवा में स्थानांतरण तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि स्थानांतरित सरकारी कर्मचारी के पास स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार न हो। मौलिक नियम 113 कहता है कि विदेश सेवा में स्थानांतरित सरकारी कर्मचारी उस संवर्ग या संवर्ग में बना रहेगा जिसमें उसे अपने स्थानांतरण से ठीक पहले एक मूल या स्थानापन्न क्षमता में शामिल किया गया था और उसे उन संवर्गों में प्राधिकारी के रूप में इस तरह की मूल या स्थानापन्न पदोन्नति दी जा सकती है। पदोन्नति का आदेश देने में सक्षम व्यक्ति निर्णय ले सकता है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के पास उस अतिरिक्त पद पर ग्रहणाधिकार था जिस पर उसकी

पुष्टि की गई थी। इसलिए, विदेश सेवा में उनका स्थानांतरण मौलिक नियम 111 के तहत स्वीकार्य था। हालाँकि, वह अपने स्थानांतरण से ठीक पहले किसी कैडर से संबंधित नहीं थे, और मौलिक नियम 113 का उनके मामले में लागू नहीं था।

अंत में, यह तर्क दिया गया है कि लोक सेवा आयोग के पास यह शर्त लगाने का कोई अधिकार नहीं था कि अपीलकर्ता के पास सचिवालय या उससे जुड़े कार्यालयों में रूटीन डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्ति का कोई दावा नहीं होगा। अपने एक अभ्यावेदन में अपीलकर्ता ने कहा कि उन्होंने उस नोट पर हस्ताक्षर किए हैं जिसने उनका ध्यान इस शर्त की ओर आकर्षित किया है कि ''यह समझा कि इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यह नियमों और सरकारी आदेशों के विपरीत है''। अपीलकर्ता का तर्क यह है कि लोक सेवा आयोग जो 1926 में गठित किया गया था और गृह विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 178ध्14ध्24 स्था. में प्रकाशित नियमों के तहत कार्य करता था। दिनांक 14 अक्टूबर, 1928, भारत में सिविल सेवा के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की भर्ती से संबंधित था, और तब लागू नियम भर्ती के संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए प्रदान नहीं करते थे। और उस अधीनस्थ सेवा का नियंत्रण जिससे अपीलकर्ता संबंधित था। इस तर्क को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। अपील पर उच्च

न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता की नियुक्ति 8 दिसंबर, 1928 को भारत सरकार के गृह विभाग के एक कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निर्देशों द्वारा शासित थी, जिसके पैराग्राफ टप्प्प् में कहा गया था.-

"विशेष मामले- ऐसे मामलों को पूरा करने के लिए जहाँ एक उम्मीदवार, हालांकि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, ने खुद को उच्च या समकक्ष मानक की परीक्षाओं में संतोषजनक ढंग से साबित कर दिया है, या मंत्रालयिक कर्मचारियों के बाहर सरकारी सेवा का अच्छा अनुभव प्राप्त किया है या किसी पद के लिए विशेष योग्यता रखता है। कार्य की विशेष श्रेणी में, लोक सेवा आयोग को अधिकार है कि (ए) निर्धारित योग्यताओं के अलावा अन्य शैक्षिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को परीक्षा में प्रवेश दे सके, और (बी) उन व्यक्तियों को परीक्षा से छूट देने या किसी विशेष डिवीजन में प्रवेश देने के लिए, जिन्हें उनके पिछले रिकॉर्ड के कारण उनकी राय में उचित रूप से छूट दी जा सकती है या जैसा भी मामला हो, प्रवेश दिया जा सकता है। पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के मामले में ऐसी कार्रवाई केवल संबंधित विभाग की सिफारिश पर की

जाएगी। इस प्रावधान द्वारा आयोग में निहित विवेकाधिकार को ध्यान में रखते हुए, अब विभाग अपने कार्यालयों या अधीनस्थ कार्यालयों के लिए विशेष या तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से भर्ती करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। ऐसी कोई भी नियुक्ति करने से पहले उन्हें लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।''

अपीलकर्ता का मामला, जिसने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, जिसकी जगह 1926 में लोक सेवा आयोग ने ली थी, संभवतः उपरोक्त पैराग्राफ के तहत लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इसमें शामिल निर्देश भी लोक सेवा आयोग द्वारा एक शर्त लगाने को उचित नहीं ठहराते हैं, और लोक सेवा आयोग केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका उल्लेख (ए) और (बी)में किया गया है।

हमारा मानना है कि वर्तमान अवसर पर इन तर्कों की वैधता की जांच करना अनावश्यक है। यह मानते हुए, लेकिन यह तय किए बिना कि अपीलकर्ता के मामले को लोक सेवा आयोग को संदर्भित करना आवश्यक नहीं था या लोक सेवा आयोग अपीलकर्ता की नियुक्ति पर कोई शर्त नहीं लगा सकता, तथ्य अभी भी बना हुआ है कि उपयुक्त प्राधिकारी जिसने

मंजूरी दी थी अतिरिक्त पद ने यह स्पष्ट कर दिया कि पद नियमित कैडर के बाहर था और महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा ने कहा कि व्यवहार में इस पद को नियमित प्रतिष्ठान के बाहर माना गया था, हालांकि प्रशासनिक नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए यह उनके कार्यालय से जुड़ा हुआ था। यह स्थिति होने के कारण, यह बहुत कम मायने रखता है कि अपीलकर्ता के मामले के संबंध में लोक सेवा आयोग के पास क्या शक्तियाँ थीं। हालाँकि, हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम असहमति व्यक्त नहीं करते हैं. ऐसा करना हमारे लिए अनावश्यक है उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार से कि अपीलकर्ता की नियुक्ति को सहमति देने में, यह लोक सेवा के लिए खुला था आयोग को सशर्त सहमति देनी होगी।

यह हमें सिविल अपील 116 में अपीलकर्ता के मामले को समाप्त करने के लिए लाता है। सिविल अपील 117 के निपटान के लिए केवल कुछ शब्द आवश्यक हैं। उस अपील के लिए किसी भी पुनरावर्ती सेवा नियम या अस्पष्ट विभागीय आदेश की गंभीर व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि अपीलकर्ता महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा सेवा के नियमित प्रतिष्ठान का सदस्य नहीं था, वह उस कार्यालय में वरिष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं था। यह सच है कि अपीलकर्ता ने विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश से डिक्री प्राप्त की थी। हालाँकि, यह केवल एक घोषणात्मक डिक्री थी, क्योंकि अपीलकर्ता ने वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि

जैसी अन्य राहतों के लिए दबाव नहीं डाला था। यहाँ तक कि जब प्रतिवादी नंबर 1 ने इसके खिलाफ अपील की तो घोषणात्मक डिक्री भी खतरे में पड़ गई। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता उसे दिए गए कार्य को करने से कैसे इंकार कर सकता है? हमने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनमें अपीलकर्ता ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग में काम करने से इनकार कर दिया था, जिसे उसे आवंटित किया गया था। उन्होंने 13 अक्टूबर 1952 से काम नहीं किया और नवंबर 1952 से उन्हें कोई वेतन नहीं मिला। अपीलकर्ता को उस परिस्थिति के लिए खुद को धन्यवाद देना होगा जिसमें वह खड़ा है। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि यदि उसने धैर्य, अच्छी समझ और संयम दिखाया होता, तो वह अपने ऊपर आई बड़ी मुसीबत से बच सकता था।

परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें विफल हो जाती हैं और लागत सहित खारिज कर दी जाती हैं; चूंकि अपीलें एक साथ सुनी गई, इसलिए दो अपीलों में उत्तरदाताओं द्वारा साझा किया जाने वाला शुल्क एक सुनवाई समान होगा।

अपीलें खारिज,

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डाॅ. सरोज सींवर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्कारण ही मान्य होगा।